

68 65

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

-1/2001 पुनरीक्षण

-1686-I/2001 प्र०३०

श्री एस. ए. के. वानपेयी को प्रस्तुत।
द्वारा आज दि. 6/9/2001 को प्रस्तुत।

अधिरक्षक
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
2-6 SEP 2001

- 1- सुश्री पारवती पत्नी केदारनाथ
- 2- शिवगोपाल } पुत्राण केदारनाथ
- 3- रामकृष्ण }
- 4- विधाता प्रसाद पुत्र हुल्बलाब
निवासीगण ग्राम परसधा तहसील त्याँथर
जिला रीवा ----- आवेदकगण
विरुद्ध

- 1- विश्वनाथ तनय महावीर
- 2- रामकान्त तनय विश्वनाथ
निवासीगण ग्राम परसधा तहसील त्याँथर
जिला रीवा ----- अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्र०३० 1874/96-97 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 12-6-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मू राजस्व संहिता 1959

महोदय,
2-6-2001

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

- (1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
- (2) यह कि प्रकरण में विवादित मूमि के अमिलिखित मूमिस्वामी आवेदकगण 1, 2 एवं 3 हैं। आवेदक क्रमांक 4 ने अमिलिखित मूमिस्वामियों से पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा मूमि क्रय की है एवं आवेदक क्रमांक 4 को नामांतरण कराने की पात्रता है। तहसील न्यायालय द्वारा अमिलेख

M


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ

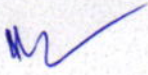
प्रकरण क्रमांक निगरानी 1686-एक/2001

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-9-2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।</p> <p>2- आवेदक अभिमाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण 1, 2 एवं 3 हैं। आवेदक क्रमांक 4 ने अभिलिखित भूमिस्वामी से भूमि कय की थी। अनावेदकगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 ने बिना किसी अधिकार के एवं अवैध कार्यवाही के माध्यम से आवेदकगण की भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया है, जिसे वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी गई। इसी बीच अनावेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 को भूमि अंतरिम कर दी। अतः अनावेदक क्रमांक 2 का तथाकथित नामांतरण स्वत्वहीन होने से उपेक्षणीय है। आवेदक क्रमांक 1, 2 एवं 3 अपने पूर्वज केदारनाथ के समय से भूमिस्वामी चले आ रहे हैं तथा नामांतरण के आवेदन का विधिवत निराकरण किया जाना चाहिए। अपर आयुक्त ने बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर की जा रही न्यायालयीन कार्यवाही को समाप्त कर देने में गंभीर भूल की है। अतः अपर आयुक्त का विवादित आदेश निरस्त किया जाये।</p> <p>3- अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपर आयुक्त ने बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये अपील को स्वीकार कर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। चूंकि अपील प्रकरण में आवेदकगण को</p>	

बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 12-6-01 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार त्योंथर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि चूंकि प्रकरण पूर्व से ही दिनांक 22-4-97 को नियत था किन्तु न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चलते लगभग 19 वर्ष से लंबित है अतः अनावेदकगण विश्वनाथ एवं रमाकांत को आहूत कर एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत नायब तहसीलदार गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दर्ज अभिलेखागार हो।


(के. सी. जैन)
सदस्य



201